भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

07.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2372 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

2372. श्री दिलीप राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास देश में रेलवे स्टेशनों से परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) को प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो स्टेशनों की संख्या कितनी है तथा ओडिशा के रेलवे स्टेशनों से इस प्रकार परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से अपेक्षित राजस्व सृजन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के विकास/आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित विभिन्न मॉडलों का पता लगाया है, जैसे मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन जिसे पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और शुरू किया गया है।

वर्तमान में, 15 स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकास के लिए चिह्नित किया गया है। इन 15 स्टेशनों में से, आंध्र प्रदेश में दक्षिण तट रेलवे के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पीपीपी मोड में पुनर्विकास का प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) को भेजा गया था। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

पीपीपी के अंतर्गत विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए बोली आमंत्रित की गई थी, लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए निविदा के लिए बोली पुनः आमंत्रित की गई है।

शेष 14 स्टेशन (कोयंबत्तूर जंक्शन, क्रांतिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेंगलुरु, चेन्नै सेंट्रल, अंधेरी, आवडि, ताम्बरम, भोपाल, वडोदरा, कल्याण, दादर, आनंद विहार, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन और पुणे) मास्टर प्लानिंग और वित्तीय मॉडलिंग के विभिन्न चरणों में हैं।

******